आलू-प्याज और चीनी के दाम भड़के

खुदरा महंगाई दर जुलाई के 4.45% से बढ़कर अगस्त में 4.82% पर आई

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 15 सितम्बर. सरकार द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में भारत की खुदरा महंगाई दर जुलाई के 4.45 फीसदी से बढ़कर 4.82 फीसदी हो गई है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खाने-पीने की चीजों की कीमतों और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अन्य इनपुट कंपोनेंट्स ने इकोनॉमी पर दबाव डाला.

ताजा आंकड़े बताते हैं कि सकल खाद्य महंगाई दर के कारण बढ़ रही महंगाई दर के बाद कम रहने के बाद अब कीमतों का दबाव बढ़ने लगा है. अर्थशास्त्रियों के रॉयटर्स पोल में इस महंगाई दर के अगस्त में 4.80 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें अनुमान 4.40 फीसदी से 5.05 फीसदी के बीच था. जुलाई में यह 3.93 फीसदी से बढ़कर 4.38 फीसदी हो गई थी.

अगस्त की महंगाई दर इस समय के बाद से सबसे ज्यादा है. जब से भारत ने इस साल की शुरुआत में नए टैक्स स्लैब और अपडेटेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ अपनी पिछली सीपीआई सीरीज अपनाई है. आरबीआई को वित्त वर्ष 2027 के लिए हेडलाइन खुदरा महंगाई दर को 5 फीसदी पर बनाए रखने का काम सौंपा गया है. इन चीजों पर निर्भर करेगी महंगाई. महंगाई का ट्रेंड दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति और खाद्य उत्पादन के अनुमान पर निर्भर कर सकता है. सब सामान्य मानसून से फसल की पैदावार बेहतर हो सकती है.

चीनी 60 रुपये के नीचे

सरकार के कई सख्त उपायों के बाद देशभर में चीनी की औसत खुदरा कीमत लगातार चौथे दिन 60 रुपये प्रति किलोग्राम से कम रही. हालांकि त्योहारों से जुड़ी मांग के कारण कुछ क्षेत्रों में कीमतों पर बढ़ने का दबाव बना हुआ है. वैसे थोक कीमतें 50 रुपये प्रति किलो के नीचे आ गई हैं, जो पिछले माह 65 रुपये के पार हो गया था. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चीनी की औसत खुदरा कीमत सोमवार को 59.57 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जो एक दिन पहले 58.99 रुपये प्रति किलोग्राम थी. शुक्रवार को चीनी की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर से नीचे आ गई थी और पिछले तीन दिनों में इसमें और नरमी आई है. मगर खुदरा कीमत अभी भी 58.23 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है. 21 अगस्त को यह कीमत इतनी थी, जब केंद्र ने पहली बार चीनी के आयात की अनुमति दी थी और मिडास देने वाली इस वस्तु की कीमतें थोक में 59 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं.

त्योहारों पर 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 15 सितम्बर. भारतीय रेल ने आगामी त्योहारी सीजन की भीड़ को देखते हुए 100 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें बिहार, प. बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश के कई व्यस्त रूटों पर चलाई जाएंगी. रेलवे सूत्रों के मुताबिक, दुर्गापूजा, दिवाली व छठ के दौरान नई ट्रेनें चलाने के अलावा नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे ताकि यात्रियों को आसानी से आरक्षित सीटें मिल सकें.

साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइटों के सर्वर भी मजबूत किए गए हैं ताकि यात्रियों को आसानी से टिकट बुकिंग सुविधा मिल सके. इसके तहत 6,000 हॉर्सपावर के नए और कम ऊर्जा खपत वाले इंजन खरीदे जाएंगे.

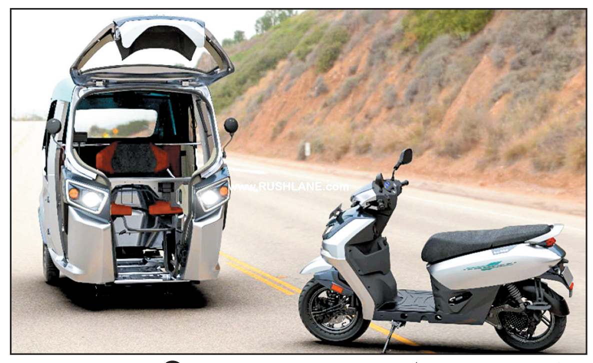

कार नहीं, स्कूटर और ऑटो चला रहे इवी मार्केट

बाजार : वित वर्ष 2025-26 में देश में करीब 24.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 15 सितम्बर. भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की बात जैसे ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक कारों का ख्याल आता है. टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियां इस बाजार में नए मॉडल उतार रही हैं. लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की असली कहानी फिलहाल कारों से नहीं बल्कि स्कूटर और ऑटो से लिखी जा रही है.

वित्त वर्ष 2025-26 में देश में करीब 24.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जो एक साल पहले के मुकाबले करीब 25 फीसदी ज्यादा हैं. इनमें अकेले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री करीब 14 लाख रही. यानी भारत में बिकने वाले हर 100 इलेक्ट्रिक वाहनों में करीब 57 दोपहिया वाहन थे. वहीं यात्री इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी भी 29 फीसदी रही.

इलेक्ट्रिक ऑटो में कमाई का गणित- ऑटो या सामान ढोने वाला तिपहिया वाहन आम निजी वाहन के मुकाबले रोज ज्यादा दूरी तय करता है. ऐसे में पेट्रोल या दूसरे ईंधन पर होने वाला खर्च काफी कम हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक कम ऊर्जा खर्च, कम रखरखाव और रोज ज्यादा इस्तेमाल के कारण इलेक्ट्रिक तिपहिया आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद हो सकते हैं. इलेक्ट्रिक तिपहिया आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद हो सकते हैं.

इलेक्ट्रिक कारें पीछे क्यों

इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री बढ़ रही है लेकिन स्कूटर और तिपहिया के मुकाबले रफ्तार धीमी है. इसकी वजह है. इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत ज्यादा होना, पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलना, रास्ते में बैटरी खत्म होने की चिंता, पुरानी इलेक्ट्रिक कार की रीसेल वैल्यू और भविष्य में बैटरी बदलने का खर्च अभी ग्राहकों के लिए बड़े सवाल हैं. हालांकि लंबी अवधि में तस्वीर बदल सकती है. रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत में बिकने वाली नई कारों में इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी करीब 15 फीसदी तक पहुंच सकती है. 2024 में यह करीब 2 फीसदी थी. इलेक्ट्रिक तिपहिया साधन का मामला और भी दिलचस्प है. ऑटो या सामान ढोने वाला तिपहिया वाहन आम निजी वाहन के मुकाबले रोज ज्यादा दूरी तय करता है. ऐसे में पेट्रोल या दूसरे ईंधन पर होने वाला खर्च काफी कम रहता है.

टाटा संस पर आरबीआई का शिकंजा

- **हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल**
- **अब सूचीबद्धता की तैयारी तेज**

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 15 सितम्बर. आरबीआई ने बंबई उच्च न्यायालय में एक कैविएट याचिका दायर की है. यह याचिका टाटा संस को अनिवार्य सूचीबद्धता से संबंधित मामले में दायर की गई है.

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत द्वारा कोई भी आदेश पारित करने से पहले आरबीआई को सुना जाए. ईटी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है. आरबीआई ने कहा है कि यदि कोई याचिकाकर्ता इस मामले में अदालत का रुख करता है, तो आरबीआई अपना पक्ष रख पाएगा. कई सूत्रों ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है. आरबीआई ने टाटा संस के मुख्य वित्तीय अधिकारी को सूचित किया है कि उनका लाइसेंस सरेंडर करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है. इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने टाटा संस का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस सरेंडर करने का आवेदन खारिज कर दिया है. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने कंपनी को तुरंत सार्वजनिक सूचीबद्धता की तैयारी करने का निर्देश दिया है. यह घटनाक्रम टाटा समूह के हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण है.

भारत-पाक समेत एशियाई देशों की टूटी कमर

गैस से बढ़ा 70 हजार रुपए का बोझ, एलएनजी पर कुल 7.4 अरब डॉलर खर्च

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 15 सितम्बर. जब से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव शुरू हुआ है, तब से खासकर एशियाई देशों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. तनाव शुरू होने से पहले जो सामान जितनी कीमत का मिल रहा था, वही अब दोगुने से ज्यादा कीमत का हो गया है.

रिपोर्ट में इस बात का जबरदस्त खुलासा हुआ है. भारत और पाकिस्तान समेत एशिया के उभरते हुए देशों का एलएनजी बिल दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार यूएस-ईरान तनाव शुरू होने के बाद से भारत और एशिया के चार अन्य बड़े उभरते एलएनजी खरीदारों ने स्पॉट एलएनजी मार्केट में कुल मिलाकर 7.4 अरब डॉलर खर्च किए हैं. यह रकम एक साल पहले लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदी गई एलएनजी की सप्लाई की कॉस्ट से दोगुनी से भी ज्यादा है.

देखना हुआ इन देशों का एलएनजी बिल एशिया में चीन के अलावा अन्य प्रमुख उभरते बाजार वाले खरीदारों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम ने स्पॉट मार्केट का रुख किया है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कतर गैस से एलएनजी शिपमेंट में संकट के कारण कॉन्ट्रैक्ट के तहत होने वाली सप्लाई ठप हो गई और कीमतें बढ़ गईं. रिपोर्ट के अनुसार इन पांच देशों ने इस अवधि के दौरान स्पॉट एलएनजी पर 7.4 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत इतनी ही मात्रा के लिए लगभग 3.1 अरब डॉलर खर्च किए गए थे.

कई देशों ने किए बदलाव

रिपोर्ट में एनालिस्ट अक्षय मोदी के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान, जिसे पहले तेजी से बढ़ते एलएनजी मार्केट के तौर पर देखा जाता था, होर्मुज में आई रुकावट के असर के कारण मोबाइल और हाइड्रोपावर पर अपनी निर्भरता बढ़ा सकता है. इस बीच बांग्लादेश ने कतर से मिलने वाली एलएनजी सप्लाई बंद होने के बाद उसकी भरपाई के लिए 2 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं और रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए इंसेंटिव भी दे रहा है. थाईलैंड ने भी एक नई लॉन्ग-टर्म एनर्जी योजना पेश की है, जिसके तहत 2050 तक अपनी कम से कम 65 फीसदी बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल करने का लक्ष्य रखा है.

बीएचईएल को लगातार तीसरे साल राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

'क' क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में मिला द्वितीय पुरस्कार

नवभारत कनेक्ट
नई दिल्ली, 15 सितंबर. राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को लगातार तीसरे वर्ष देश के प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

वर्ष 2025-26 के कीर्ति पुरस्कारों में बीएचईएल को 'क' क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया. यह सम्मान गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से दिया जाता है और राजभाषा के क्षेत्र में देश के प्रमुख राष्ट्रीय सम्मानों में शामिल है. पुरस्कार समारोह 14 सितंबर को महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान हुआ.

इस अवसर पर बीएचईएल के निदेशक (पावर) एवं अतिरिक्त प्रभार (मानव संसाधन) तजिंदर गुप्ता ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार से पुरस्कार ग्रहण किया.

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार का उद्देश्य सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदी के बेहतर इस्तेमाल तथा राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना है. बीएचईएल देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शामिल है और विद्युत क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण उपकरणों एवं परियोजनाओं के निर्माण में इसकी अहम भूमिका है. लगातार तीसरी बार मिले इस सम्मान से कंपनी ने राजभाषा के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान कायम की है.

भारतीय कारों पर घटेगा शुल्क

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 15 सितम्बर. भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए में भारतीय कारों के लिए यूरोपीय बाजार का रास्ता आसान करने का प्रावधान किया गया है. समझौते के मसौदे के अनुसार, पहले साल भारत में बनी 2.5 लाख यात्री कारों को यूरोपीय संघ के बाजार में 8 प्रतिशत रियायती शुल्क पर प्रवेश मिलेगा. यह संख्या धीरे-धीरे बढ़कर समझौते के 10वें साल से 4 लाख वाहन सालाना हो जाएगी.

पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट में हुई भारी बढ़ोतरी

- **चीन फूल कर रहा है तेल की टंकी**

नवभारत न्यूज नेटवर्क.
नई दिल्ली, 15 सितम्बर. कच्चे तेल की कीमत में भारी तेजी के बीच चीन अपना तेल भंडार को फिर से भरने की कोशिश कर रहा है. अगस्त में चीन का कच्चा तेल आयात 22 लाख टन बढ़कर 3.79 करोड़ टन हो गया, जो लगातार दूसरे महीने हुई बढ़ोतरी है.

कच्चे तेल की कीमत में साल के में बढ़ोतरी में चीन के आयात की भी अहम भूमिका रही है. ईरान युद्ध के बाद जब कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था तो चीन ने आयात में कमी करके विदेशी मुद्रा बचाई थी. इस दौरान उसने अपने तेल भंडार का यूज किया.

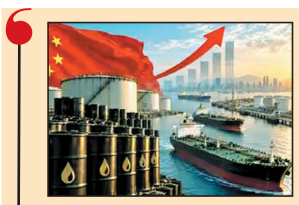

दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार

दिखाई दे रहा है कि चीन का तेल आयात पिछले साल के मुकाबले 23% बढ़ा है और इस साल के सबसे ऊंचे स्तर से 32% नीचे है. चीन के आधिकारिक कस्टम डेटा के अनुसार, अगस्त में चीन ने 37.93 मिलियन टन यानी रोजाना 8.93 ... जुलाई की तुलना में 6.2% ज्यादा है. जून में यह ... चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. एक अनुमान के मुताबिक यह 1.2 अरब बैरल से ज्यादा है. दूसरे देश को कीमतें बढ़ने पर खरीदारी कम करने की काफी गुंजाइश मिलती है.

समाचार विशेष

रावत का संन्यास या नया समर

अगले कदम पर भाजपा-कांग्रेस दोनों की नजर

देहरादून. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं.

चुनावी मोड में आ गए उत्तराखंड के राजनीतिक अग्निकुंड में उनके बयानों की आहुति ने अलग दिशा और मुद्दा पकड़ा कर और प्रज्वलित कर दिया है. उनके अगले कदम की प्रतीक्षा जितनी भाजपा नेताओं को है उससे अधिक कांग्रेस को है. रावत के कुछ दिनों पहले दिए गए बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था संन्यास छुप-छुपाकर नहीं लूंगा और मेरे कुछ चितकबरे 'चहेतों' ने मुझसे सक्रिय राजनीति से संन्यास दिलवाने की सुपारी ले रखी है.

स्पष्ट है कि साठ वर्षों के संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन जिसमें कुमाऊं के उतार-चढ़ाव के बाद गढ़वाल से सम्मानपूर्वक विदाई की आस और राजनीतिक संन्यास की चाह जरूर रखते होंगे. ऐसे में अगर आलाकमान ने उनकी पेशकश पर मुहर लगा दी तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका राजनीतिक संन्यास भी माना जाएगा. ईडी का हरीश रावत के ओएसडी रहे चंदन सिंह जीना के ठिकानों पर छापा उनके यहां से नकदी और अन्य कीमती चीजों की बरामदगी उनके शेष राजनीतिक सफर का पीछा करेगी. रावत भले ही खुद को पार्टी के पदों पर बने रहने से राहुल गांधी के भ्रष्टाचार की लड़ाई में बाधा के रूप में देख रहे हैं लेकिन पार्टी में उनके संन्यास की सुपारी ले चुके उनके चितकबरे चहेते को राजनीतिक अवसर मिला है.

जीना के ठिकानों पर छापा यूकेएसएसएससी वीपीडीओ भर्ती परीक्षा 2016 में ओएमआर शीट से छेड़छाड़, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है ऐसे में शुद्धिकरण को लेकर घिरी भाजपा को चुनावी हथियार के रूप में दाग मिल गया है.

फिर राजनीतिक परीक्षा

हरीश रावत ने अपने जीवन में कई राजनीतिक लड़ाइयां लड़ीं. कई चुनावी हार के बाद भी टूटे नहीं और सक्रियता बनाए रखी. उनकी पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें बहुत मौके भी दिए और विश्वास भी किया है. रावत ने पार्टी के अन्य नेताओं की तरह कभी चोला भी नहीं बदला. अब उन्हें फिर राजनीतिक परीक्षा से गुजरकर खुद को पार्टी के सामने नए तरीके से अपने को सदस्य साबित कर नए समर में उतरना होगा.

झारखंड भाजपा में जयराम इफैक्ट

कुड़मी नेताओं को संगठन में मिली जिम्मेदारी

रांची. भारतीय जनता पार्टी अपने आधार वोटबैंक को बढ़ाने के लिए ओबीसी समुदाय की प्रमुख जातियों को संगठन में प्रतिनिधित्व दे रही है. पहली बार कुड़मी समुदाय के नेता को ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

मनोज महतो को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. जबकि प्रदेश की मुख्य कमेटी में भी कुड़मी समुदाय के दो नेताओं को रखा गया है. प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो कुड़मी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज के सामने मजबूती से पार्टी की बात रखते हैं.

कुड़मी समुदाय के वोट के लिए भाजपा अपने सहयोगी दल आजसू पर अबतक निर्भर रहती आई है. इसके अलावा जयराम महतो के राजनीतिक उभार से भी कुड़मी समुदाय की राजनीति से भाजपा की दूरी हुई थी. अब इस अंतर को पाटने के लिए भाजपा अपने नेताओं को आगे बढ़ा रही है. इसके अलावा कोल्हान से लेकर धनबाद के कोयलांचल तक जिला कमेटियों में भी कुड़मी नेताओं को दस प्रतिशत तक प्रतिनिधित्व दिया गया है.

निकाय चुनाव में भाजपा की भारी फजीहत!

जयपुर. राजनीति की बिसात पर हार-जीत के किस्से तो आपने कई सुने होंगे. लेकिन राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले से निकली यह चुनावी दास्तान दिलचस्प है. साथ ही हैरान करने वाली भी है.

परबतसर नगर पालिका चुनाव के नतीजे जब सब सामने आए, तब भाजपा उम्मीदवार के नाम के आगे लिखा केवल 1 वोट, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. वार्ड नंबर वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कैलाश चंद्र को महज एक वोट मिले. कुल 573 वोट पड़े, मगर ईवीएम खुली तो कैलाश चंद्र के हिस्से में सिर्फ एक अकेला वोट दर्ज हुआ. अचरज की बात यह रही कि कैलाश चंद्र जिस वार्ड से चुनावी दंगल में उतरे थे, वहां की वोटर लिस्ट में उनका अपना नाम था ही नहीं. उनके अपने परिजन और सगे-संबंधी तो दूसरे वार्ड में मतदाता थे, ऐसे में जिस वार्ड में प्रचार का पसीना बहाया, वहां अपनों का एक भी वोट नहीं मिल सका. नतीजा यह हुआ कि पूरे वार्ड से सिर्फ एक अनजान वोटर ने उन पर भरोसा जताया और इस एक वोट के दिलचस्प आंकड़े ने पूरे राजस्थान निकाय चुनाव का सबसे अनोखा किस्सा गढ़ दिया.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
कॉर्पोरेट मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003

मध्यस्थ का पैनल में शामिल किया जाना

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने "AAI से जुड़े कानूनी मामलों, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से पैदा होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ (Arbitrator) की नियुक्ति (Empanelment)" के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉर्म AAI की आधिकारिक वेबसाइट पर 10.09.2026 सुबह 09:30 बजे से 09.10.2026 शाम 06:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। योग्यता के मानदंडों और नियुक्ति (empanelment) से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.aai.aero → Career → Recruitment Dashboard पर जाएं।

cbc03111/11/0007/2627

विशेष | **राव इंद्रजीत खेमे की दूरी से बढ़ी चिंता, सैनी के कार्यक्रम पर टिकी नजरें**

हरियाणा भाजपा में अंदरूनी खींचतान

नारनौल. बेशक हरियाणा में अभी चुनाव ढाई साल बाद होंगे पर राजनेताओं ने अभी से रणनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है. इसका असर राजनीतिक दौरों और राजनेताओं के बयानों से साफ झलक रहा है. हर कोई अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा है तो विरोधियों को कमजोर करने की कवायद पर्दे के पीछे चल रही है.

हरियाणा की सत्ता बनाने वाले दक्षिण हरियाणा की राजनीति पिछले दो माह से गर्माई हुई है. इस गर्माहट के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सक्रियता बढ़ गई है. मुख्यमंत्री 17 सितंबर को तीसरी बार महेंद्रगढ़ जिले में आ रहे हैं तो रेवाड़ी में भी दो बार बड़े कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं.

माना जा रहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पार्टी के नेताओं के बीच पैदा हुई राजनीतिक खाई को पाटने में लगे हैं. मुख्यमंत्री के महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में केवल एक कार्यक्रम को छोड़ दें तो तीन में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व उनके समर्थक दिखाई नहीं दिए. नारनौल में नौ अगस्त को आयोजित की गई हाफ मैराथन में ही स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव शामिल हुई थीं. इसके बाद 23 अगस्त को लाजिस्टिक हब के रेल यार्ड के उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री नहीं पहुंच पाई थी. हालांकि उस समय बताया गया था कि स्वास्थ्यमंत्री का पहले से कोई और कार्यक्रम निर्धारित था. संभावना जताई जा रही है कि 17 सितंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री पहुंच सकती हैं. अब इसे संयोग कहें या फिर कोई राजनीतिक मायने निकाले जाएं कि 23 अगस्त के कार्यक्रम के बाद रेवाड़ी में हुई हाफ मैराथन में भी स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बनाई हुई थी.

बड़ी राजनीतिक हलचल का संकेत

सवाल उठता है कि क्या दक्षिण हरियाणा में मुख्यमंत्री की सक्रियता किसी बड़ी राजनीतिक हलचल का संकेत दे रही है. माना जा रहा है कि खेमेबाजी में जोर देने वाले नेताओं को पार्टी के लिए एकजुट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. यहां यह भी स्पष्ट कर दें कि हरियाणा का राजनीतिक इतिहास बता रहा कि दक्षिण हरियाणा जिस ओर करवट लेता है, उसी की सूबे में सरकार बनती है. वर्तमान में भाजपा में ही रहकर कई नेता एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं. नेताओं के बीच तीखे व्यंग्य चल रहे हैं.